DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 27 जून, 2023 ----------DATED----------

50 साल की हुई एशिया की सबसे बड़ी आइटी मार्केट

शिवांगी चंद्रवंशी • दक्षिणी दिल्ली

एशिया के सबसे बड़े आइटी मार्केट के नाम से मशहूर नेहरू प्लेस को इस वर्ष 50 साल पूरे हो गए। इस अवसर पर मार्केट को दुल्हन की तरह सजाने की तैयारी चल रही है। डीडीए सुंदरीकरण का काम करा रहा है। 90 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है। बाकी बचे कार्य जल्द पूरे कर लिए जाएंगे। 1972 में डीडीए ने 94 एकड़ में फैले इस डिस्ट्रिक्ट सेंटर का निर्माण करवाया था, जिसे बाद में एसडीएमसी को हैंडओवर कर दिया था। यहां छोटे-बड़े करीब 15 हजार दुकानें व आफिस हैं, जिनमें दो से तीन लाख लोग काम करते हैं। तीन लाख से अधिक लोग प्रतिदिन यहां खरीदारी करने आते हैं।

पिछले 50 सालों में यहां के भवन, बेसमेंट व पार्किंग एरिया व सीढ़ियां काफी जर्जर हो चुकी थीं। दुकानदार मरम्मत व सुंदरीकरण की मांग कर रहे थे। वर्ष 2019 में निगम की ओर से मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू किया गया था।

क्या-क्या किया गया बदलाव : 200 करोड़ के प्रोजेक्ट का कार्य 2019 से किया जा रहा है। नवीनीकरण में इसकी फर्श से लेकर बिल्डिंगों की रंगाई-पुताई तक का काम किया गया है। सेंटर के सभी 110 भवनों की रंगाई व सीढ़ियों की मरम्मत की जा चुकी है। मार्केट परिसर में एक मिनी थियेटर बनाया गया है। इसके अलावा एक मल्टीलेवल पार्किंग, मेट्रो से मार्केट तक स्काईवाक व पूरे परिसर में 10 सार्वजनिक शौचालय बनवाए गए है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर के खुले क्षेत्र में टूट चुकी पुरानी टाइल्स को बदलकर नए पत्थर लगा दिए गए है। मार्केट को सुंदर दिखाने के लिए सफेद रंग की कैनोपी का इस्तेमाल किया गया है।

नेहरू प्लेस मार्केट परिसर में लगे कैनोपी • जागरण

- नेहरू प्लेस मार्केट का जोर-शोर से सुंदरीकरण का चल रहा काम, 90% काम पूरा
- 94 एकड़ में फैले इस डिस्ट्रक्टि सेंटर का डीडीए ने 1972 में करवाया था निर्माण
- 15 हजार दुकानें व आफिस हैं यहां पर, जिनमें दो से तीन लाख लोग करते हैं काम

मार्केट परिसर में लगा जी-20 का लोगो • जागरण

नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन से जोड़ने के लिए स्काइवाक : नेहरू प्लेस मार्केट से नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन आने-जाने के लिए लोगों को डिवाइडर फांदना पड़ता है। इससे जाम भी लगता है। मार्केट व मेट्रो स्टेशन को जोड़ने के लिए यहां एक स्काइवाक बनाया जा रहा है। डीडीए के अधिकारी के अनुसार, इसका 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। अगले माह तक इसे राहगीरों के लिए चालू किया जाएगा।

यहां पीक टाइम में सर्विस लेन तक वाहन खड़े रहते हैं, जिससे आउटर रिंग रोड पर जाम भी लगता है। इस समस्या को दूर करने के लिए मार्केट के सामने आउटर रिंग रोड की ओर एक बहुमंजिला कार पार्किंग का निर्माण करवाया गया जा रहा है। इसमें 800 कार पार्क की जा सकेंगी। पार्किंग का रखरखाव व संचालन निगम की ओर से किया जाएगा। थोड़ी देर के लिए आने वाले ग्राहकों के वाहन मार्केट में स्थित अलग-अलग सर्फेस पार्किंग में पार्क किए जा सकेंगे। सुंदरीकरण का कार्य पूरा होने पर नेहरू प्लेस कंप्यूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल ने खुशी जाहिर की।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 27 जून 2023

बारिश ने बढ़ाया सिग्नेचर व्यू में रहने वालों का डर

लोग चाहते हैं जल्द समाधान, 2 जुलाई को है मीटिंग

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

60 से 70 फ्लैट डर के चलते खाली किए, किराए पर रहते हैं अब लोग

2 विकल्प डीडीए ने अपार्टमेंट के लोगों को दिए, जिस पर बननी है सहमति

14 जून को हुई बोर्ड मीटिंग के बाद अब तक नहीं मिला ऑफर लेटर

'हर बारिश हमारे दिल में डर को बढ़ा देती है। छह महीने बाद भी डीडीए की तरफ से पुनर्वास में देरी हो रही है।', यह कहना है द्वारका के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में रहने वाले गौरव पांडे का। मॉनसून की पहली बारिश होने पर एनबीटी ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के लोगों से बात की। लोगों के अनुसार वह डर के साए में जी रहे हैं। फिर भी डीडीए लगातार देरी कर रहा है।

लोगों की मानें तो मॉनसून से पहले यह अपार्टमेंट खाली करवा देना चाहिए था। करीब 60 से 70 फ्लैट्स ख़ाली हो चुके हैं और लोग किराए पर रह रहे हैं। वहीं डीडीए से रीडिवेलपमेंट का फाइनल प्रपोजल मिलने के बाद आरडब्ल्यूए ने 2 जुलाई को जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई है।

अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई : जनवरी में खराब क्वालिटी की वजह से एलजी वीके सक्सेना ने इस अपार्टमेंट को रीडिवेलप करने का आदेश जारी किया था। साथ ही बिल्डिंग के निर्माण मे अनदेखी में दोषी अधिकारियों को पहचानकर विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे। लोगों का सवाल है कि सीबीआई तक में मामला गया लेकिन अब तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

क्या हैं डीडीए के 2 विकल्प

1. रेजिडेंट्स के अनुसार बॉयबैक में लोगों को फ्लैट्स की पूरी कीमत के अलावा पजेशन लेटर से लेकर अब तक का हर महीने 10.6 प्रतिशत तक का ब्याज मिलेगा। यह कीमत फ्लैट्स की मौजूदा कीमत से काफी कम है।

2. दूसरा, यहीं सेम साइज का फ्लैट देने का विकल्प है। रीडिवेलपमेंट में करीब तीन साल लगेंगे। एचआईजी वालों को 50 हजार और एमआईजी वाले लोगों को 38 हजार का रेंट हर महीने मिलेगा। डीडीए ने शर्त रखी है कि सभी फ्लैट मालिकों को किसी एक विकल्प को चुनना होगा। लोगों का कहना है कि जब 70 प्रतिशत लोगों की मंजूरी जरूरी है तो शर्त क्यों लगाई जा रही है।

“ डीडीए लगातार देरी कर रहा है। लोग कब तक परिवार के साथ इस असुरक्षित बिल्डिंग में रहेंगे। मॉनसून आ गया है, अब हर समय डर बना रहता है।

-अमरेंद्र कुमार, प्रेजिडेंट, सिग्नेचर व्यू

“ किसी न किसी फ्लैट्स से कुछ गिरने की शिकायत आती रहती है। सभी लोगों को राजी करने की शर्त पर हमें राहत चाहिए। क्योंकि यह बड़ी अड़चन है।

-गौरव पांडे, जनरल सेक्रेटरी, सिग्नेचर व्यू

“ हर बारिश में बिल्डिंग का कुछ न कुछ हिस्सा झड़ता व गिरता रहता है। इसलिए हम लोग काफी सावधानी के साथ रह रहे हैं।

-रूपेश

“ मॉनसून आते ही डर बढ़ गया है। डीडीए अब जल्द हमें ऑफर लेटर दे ताकि पूरा प्रपोजल पता चल सके और उसके अनुसार आगे बढ़ सकें।

-भूपेंद्र चौधरी

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE INDIAN EXPRESS, TUESDAY, JUNE 27, 2023 ----------DATED----------

PAGE 1
ANCHOR

Delhi's showpiece Deer Park to be shut down, its deer to be shifted

ABHINAYA HARIGOVIND
NEW DELHI, JUNE 26

A PICNIC spot with deer frolicking about, a canvas for a photoshoot, a place where fireflies would gather in the dead of the night — the Deer Park in Delhi's Hauz Khas has meant different things to different people over its 55 years in existence. But now, it is the end of a city institution as we know it.

The Central Zoo Authority (CZA), in a recent order, canceled A N Jha Deer Park's recognition as a 'mini zoo' — effectively ordering its closure — *The Indian Express* has learnt. And the nearly 600 deer it houses will be shifted to forest areas in Rajasthan and Delhi to augment their prey base. The Delhi Development Authority (DDA), under whose jurisdiction it falls', will maintain the park as a protected forest.

Behind this twin move is the "overcrowding" at the park — its deer population has grown unchecked over the years because of the absence of a natural predator. The park, which houses deer, rabbits and ducks, is an oasis of green amid the increasingly crowded neighbourhoods abutting it.

The initial proposal in 2022 was to transfer all its deer to forest areas in Rajasthan. Authorities decided at a CZA meeting in January that some of the deer would be moved to Delhi's Asola Bhatti Wildlife Sanctuary, as reported by *The Indian Express* in March.

At this meeting held under the chairmanship of the CZA Member Secretary to discuss the proposal of transferring the deer and cancelling recognition of the park, Chief Wildlife Warden of Delhi Suneesh Buxy had said that the "number of leopards in the Asola Bhatti Wildlife Sanctuary, Delhi, has risen," and "there is a need to supplement the prey base," according to the CZA's order.

The park is home to around 600 deer. These animals will be moved to forest areas in Rajasthan and Delhi. *File*

"Accordingly, requested that the spotted deer (Axis axis) from the zoo may be translocated in the sanctuary," the order recorded as a comment from Buxy.

The CZA Member Secretary had then said that the spotted deer population, which was identified to have been 565 in the DDA's communications to the CZA in 2022, may have increased to around 600, and "the same shall be transferred in ratio (70:30) to the Rajasthan Forest Department & Forest Department of NCT of Delhi respectively."

On why the closure of the deer park was necessitated, a senior DDA official said that a few deer were brought to the park in the 1960s and the increase in numbers since then has meant that the DDA's officers were not trained to handle the large numbers.

Asked when the animals are likely to be moved out of the park, the official said that would be up to the forest department officials in Rajasthan and Delhi.

A senior official of the Forest Department in Delhi said that it is now the breeding season for the animals and the deer can only be moved after the breeding season is over, possibly in winter or after the winter. "They need space for movement, along with grass and plants for foraging. This makes the Asola Bhatti Wildlife Sanctuary a good habitat for the deer," the official said.

A senior official of the Rajasthan forest department said the deer will be moved to reserves including the Mukundra and Ramgarh-Vishdhari tiger reserves, for "prey-base augmentation".

Responding to an observation from the CZA's Technical Committee that the zoo site is

CONTINUED ON PAGE 4

Delhi's Deer Park

"an important urban green space and therefore, it should be preserved", the DDA had said at the meeting in January that the site is notified as protected forest and will be preserved and maintained as forest.

The order noted that protocol prescribed by the CZA and guidelines of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) on 're-introduction and other conservation translocations' are to be followed.

The CZA's order also said that the recognition of the Deer Park was valid up to August 2021, and an application for renewal of recognition was received in September 2021 from the DDA. To ensure compliance with norms, the CZA had deputed an officer to evaluate the zoo in April 2022, and this evaluation was carried out in September 2022. In the meantime, the CZA received correspondence from the Chief Wildlife Warden of Rajasthan, addressed to the Principal Commissioner (Personnel, Horticulture and Landscape) of the DDA, on the "acquisition of 550 chital" from the deer park, according to the order.

The evaluation report and the proposal for transfer of the animals was then considered by the CZA's Technical Committee in September last year.

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 27 जून 2023

तालाब में बरसाती पानी पहुंचाने वाले नाले को किया गया ठीक

■ **विस, नई दिल्ली :** मॉनसून के बीच द्वारका के पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने संबंधित अथॉरिटी के साथ मिलकर द्वारका सेक्टर-23 के प्रदूषित हो चुके तालाब में बरसाती पानी जाने वाले नाले को ठीक कर दिया। लोगों ने करीब दो घंटे तक मशक्कत की। लोगों के अनुसार, तालाब में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का गंदा पानी भर गया था। इस वजह से बड़ी संख्या में मछलियां मर गई थीं। तालाब को लोगों ने लंबे प्रयास के बाद जीवित किया था। पिछले दिनों पता चला कि सड़क बनाने के दौरान बरसाती नाले को भर दिया गया है। जिसकी वजह से तालाब में बरसाती पानी जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। लोगों ने इसकी शिकायत डीडीए व अन्य विभागों से की। ग्रीन सर्कल से जुड़े एस. एस. मान, विशाल लाल आदि लोगों ने बताया कि नाले के टूटने की सूचना तुरंत विभाग तक यह पहुंचाई और इसे ठीक किया गया।

द्वारका सेक्टर-23 के तालाब को साफ करने के लिए पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने की पहल

करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद बरसाती नाले को ठीक किया गया

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times

----------DATED----------

Society to take call on DDA's package

Snehil Sinha
snehil.sinha@hindustantimes.com

NEW DELHI: Residents of the crumbling Signature View Apartment (SVA) in north Delhi's Mukherjee Nagar, which is supposed to be evacuated and dismantled soon, received the formal rehabilitation offer letter from the Delhi Development Authority (DDA) on Monday.

The residents will now hold a meeting on July 2 to take a call on the terms of agreement before they take a decision to move out.

The development authority has offered two options to residents — buy back and reconstruction. The terms of both options have been agreed upon by the residents' welfare organisation (RWA), according to DDA officials.

Residents are now hoping that they get a month's time before vacating the society to give them enough time to look for accommodation so that they can start moving out.

"Most residents agree with the terms offered by DDA — whether for reconstruction or for buy back. We just have to discuss which option residents would prefer. We will take a final call in our general body meeting on July 2. We just want that around a month's time be given to residents to hunt for rented accommodation and move out," said Amrendra Jha, president of SVA RWA.

Construction of the Signature View apartment began in 2007 and the first flats were allotted in 2011. According to residents, the first incidents of falling grit wash plaster and cracks in walls started appearing as early as 2013. They have also witnessed parts of the ceiling collapsing in at least 26 flats in five blocks, peeling of plasters, CC of roofs of flats, cracks in beams, walls, roof, balconies, drawing rooms, kitchen and washrooms.

The apartment is located on the main road barely 1.5km from GTB Nagar Metro station and less than 4km away from the North Campus of Delhi University.

In January, lieutenant governor VK Saxena directed DDA to "vacate and dismantle" the 12 towers of Signature View after an IIT-Delhi report deemed it unfit for habitation.

Hindustan Times
04 SPOTLIGHT | SIGNATURE VIEW TOWERS
Life, in a crumbling apartment complex
'WE COULD HARDLY SLEEP IN THAT HOUSE'
'Were watching TV in drawing room when the ceiling fell'
2.83 hectares AREA
336 FLATS
12 TOWERS
THAT GOD WAS KEPT

JUNE 15, 2023: HT spoke to Signature View residents, who get by each day with valuables packed for an emergency evacuation

DDA HAS OFFERED TWO OPTIONS TO RESIDENTS OF SIGNATURE VIEW — BUY BACK AND RECONSTRUCTION. THE TERMS OF BOTH OPTIONS HAVE BEEN AGREED UPON BY THE RWA

In its offer letter to the residents, DDA said that under the buy back option, DDA will refund the cost of capital to flat owners, excluding maintenance charges. It will also pay a simple interest of 10.6% per annum on the cost of capital from the date of each payment till June 14 this year, which is when the proposal was approved by DDA. Officials said that this payment will be made after submitting proof of payment and a no dues certificate for property tax, and electricity, water and PNG bills.

For those who opt for reconstruction, DDA will pay monthly rental of ₹50,000 to HIG (high-income group) residents and ₹38,000 to MIG (middle-income group) residents for a period of three years or till the date of offer of allotment, whichever is earlier, from the day the residents hand over their vacant flats.

The new offer also states that the carpet area of the newly-constructed flats will not be reduced. However, additional floors will be added to various towers for constructing 144 more flats. DDA will also construct a separate block with 118 EWS flats that it will allot as per its policy.

DDA has also offered to extend the balcony size by two metres on payment of additional charges. Additionally, for those who have one or no parking, DDA will also be making more parking lots, which will be allotted through an e-auction process.

"The letter has been sent to residents regarding the two proposals mentioned in the authority meeting. In all cases, a tripartite agreement with the conditions and the option selected by the residents will be signed by the DDA, flat owner and RWA," said a DDA official, asking not to be named.

Officials added that the draft tripartite agreement and the related documents are being finalised and will be sent to residents soon.

"In the meanwhile, RWA is requested to quickly reach a consensus about the option to be exercised by each allottee/owner. This proposal will be executed only after the written consent by each of the 336 allottees to exercise one of the two options of buy back or reconstruction," said the DDA letter. It added that every flat owner will also have to submit an undertaking and an indemnity bond that their flat is free from all encumbrances.